

—better quality, better yield, conservation of soil and also saving of water—and to find out whether that method will be applicable to India. What is the answer to that ?

AN HON. MEMBER : The hearing aid is not working.

MR. SPEAKER : They will attend to it and correct it.

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We have some information with regard to this particular method of irrigation. It is very expensive. The per-acre expenditure comes to anything between Rs. 3,000 to 7,500. It may be good for the particular conditions in Israel. Of course, we have certain tracts like Rajasthan where we may try some experiments. As I said, after preliminary examination of its feasibility, ICAR can go into this problem.

SHRI SAMAR GUHA : The hon. Minister informed us that they have got the information only through the bulletin published by the Israel Government. At the same time, he gave his conclusion that this method is very expensive. Is this the theoretical knowledge they have gathered from the literature ? If the Government is not prepared to send any team right now, would they agree to send some Sarvodaya people who are very much interested in it to go to Israel and study the feasibility and applicability of this method to Indian conditions ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : I do not at this stage anything can be said on that.

SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : In view of the fact that we have Israel consulate in our country, may I enquire of the Minister whether he would be in a position to make a detailed enquiry from that consulate about this system of drip irrigation and then try to follow it up here ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : As I have already submitted, we have really a large number of technicians and experts who know something on this subject, and I do not think the stage has come when it

is necessary to bring something from Israel immediately with regard to this.

SHRI VIKRAMCHAND MAHAJAN : The hon. Minister just now said that the cost of this system would be between Rs. 3,000 to Rs. 7,000 per acre. The fact is, this system increases the yield and also conserves water supply. Our Ministry is incapable of devising new methods of its own. It declines even to copy good methods which are followed in other countries. What harm would come to the Government if this system is thoroughly at least studied and a team is sent to that country so that we can at least copy a good system that is followed in that country ?

SHRI ANNASAHIB SHINDE : We are not closing our eyes to developments in any part of the world. All beneficial developments that are taking place we shall try to examine and make use of. As I have already indicated, we are trying to examine this. Unless we know the feasibility under Indian conditions we cannot follow it.

### बीड़ी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

\*1299. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के लिए एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बीड़ी श्रमिकों की मजूरी दरें न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अधीन निश्चित की गई हैं और ये कानून लागू की जाती हैं । इस अधिनियम में पुनर्विचार और संशोधन की व्यवस्था है । ऐसा समझा जाता है कि इस उद्योग के लिए असाविधिक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड उम्भूत नहीं है ।

श्री रामाबत्तार शास्त्री : मंत्री महोदय के जवाब से ऐसा लगता है कि सरकार बीड़ी मजदूरों के लिए मजदूरी बोर्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है। वह जानते हैं कि हमारे देश में बीड़ी बनाने वाले लाखों मजदूर हैं, जिन में छोटे-छोटे बच्चे और औरतें भी हैं। उन्होंने कहा है कि बीड़ी मजदूरों के लिए निम्नतम मजदूरी कानून है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह कानून प्रान्तों में लागू भी है; अगर नहीं, तो फिर उस को लागू करवाने के लिए उन के पास क्या तरीका है, ताकि बीड़ी मजदूरों को इस कानून के मुताबिक सम्बन्ध मिल सके ?

श्री हाथी : इस अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों के अधीन है और राज्य सरकारों ने इस को लागू किया है। एक महीना पहले हम ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिस में सब राज्यों को यह अधिनियम—मिनिमम वैजिज ऐक्ट—लागू करने के लिए कहा था।

श्री रामाबत्तार शास्त्री : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह कानून लागू है। क्या सरकार सदन के सामने यह जानकारी रखने की स्थिति में है कि अलग-अलग राज्यों में बीड़ी मजदूरों के लिए क्या रेट तय है और वास्तव में उन को कितनी मजदूरी मिल रही है ?

श्री हाथी : हम ने सब राज्यों की जो मीटिंग बुलाई थी, उस में इस बारे में बातचीत की गई थी। हम ने सब राज्यों से इस सम्बन्ध में हकीकत मांगी थी। यह ठीक है कि हर एक स्टेट में बीड़ी मजदूरों के अलग-अलग दर हैं; वे समान नहीं हैं। कहीं तीन रुपये हैं, कहीं दो रुपये हैं, कहीं एक रुपया भी है और कहीं इस से भी कम है। मैं ये सब आंकड़े मंगा कर जरूर दे दूंगा।

श्री अ० सि० सहगल : मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीड़ी के पत्ते और बीड़ी का कार्य बहुत बड़े पैमाने

पर चलता है। लेकिन जो बोर्ड बनाया गया है, उस के नियम के मुताबिक काम करने वालों को पैसा नहीं मिलता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है।

श्री हाथी : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह ठीक है, लेकिन हम ने कोई बेज बोर्ड नहीं बनाया है। जैसा कि उत्तर में कहा गया है, बीड़ी मजदूरों की मजदूरी मिनिमम वैजिज ऐक्ट के अनुसार तय की जाती है।

श्री भारद्वाज राय : मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने सब राज्यों की एक बैठक बुलाई थी और उन को सूचना मिली है कि अलग-अलग राज्यों की वेतन दरों में फर्क है। केवल दो राज्यों की वेतन-दरों में ही फर्क नहीं है, बल्कि एक राज्य के अलग-अलग अंचलों, एक ही शहर की अलग-अलग जगहों की वेतन-दरों में फर्क है। माननीय मंत्री जब इस फर्क को मानते हैं, तो एक नेशनल बेज बोर्ड बना कर सारे देश के लिए एक समान नीति निर्धारित करने में क्या दिक्कत है ?

श्री हाथी : बीड़ी के उद्योग में पंच, दस आदमी एक स्थान पर काम करते हैं, अपने घरों में काम करते हैं और उन में छोटे बच्चे भी हैं। यह तो राज्यों पर निर्भर है। जब तक सब राज्य न मिलें, तब तक इस बारे में कुछ करना मुश्किल है।

#### Consumer Price Index

+

\*1300. SHRI K. RAMANI :  
SHRI K. M. ABRAHAM :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4673 on the 21st March, 1968 and state :

(a) whether Government have since considered the report of the Expert Committee on consumer price index ;

(b) if so, the decision taken thereon ; and

(c) if not, when the consideration is